हिन्दू (20-01-23) राष्ट्रीय

⇨ एचसी जज के रूप में समलैंगिक वकील की नियुक्ति पर एससी कॉलेजियम फर्म।

समाचार में व्यक्ति
↓
सौरभ किरपाल → एक समलैंगिक वकील हैं
↓ ↓ → एलजीबीटीक्यू कार्यकर्ता।
एक स्विस के साथ संबंध में।

13 अक्टूबर, 2017 → दिल्ली हाईकोर्ट ने सौरभ किरपाल के लिए जजशिप की सिफारिश की
11 नवंबर, 2021 → सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जजशिप को मंजूरी दी।
25 नवंबर, 2022 → सरकार ने फाइल को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिया।

SC ने बताया कि एक व्यक्ति अपने यौन रुझान को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र है। इसने अबो बताया कि स्विट्जरलैंड एक मित्र देश है इसलिए कोई समस्या नहीं है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है?
SC कॉलेजियम ने मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली

⇨ न्यूजीलैंड की पीएम जैसिंडा अर्डर्न ने पीएम पद छोड़ने की घोषणा की है।
उसका निर्णय व्यक्तिगत है। वह 42 साल की हैं। COVID-19 2019 मस्जिद हमले और कई अन्य मुद्दों से निपटने के लिए उनकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई है। वह कुछ हफ्तों में पद छोड़ देंगी।

⇨ ज़ेलेंस्कली ने पश्चिमी सहयोगियों से और अधिक टैंक भेजने का आग्रह किया

- ज़ेलेंस्की दावोस में WEF (विश्व आर्थिक मंच) में वीडियो लिंक के माध्यम से बात कर रहे थे।
- उन्होंने जर्मनी, अमरीका और पोलैंड जैसे देशों की आलोचना की कि वे पर्याप्त हथियार नहीं भेज रहे थे, और केवल काम से प्रेरित थे।
- अमेरिका के पास अब्राम टैंक हैं, जर्मनी के पास तेंदुए के 2 टैंक हैं जो काफी प्रभावी हैं।

- उन्होंने यह भी कहा कि रूसी द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईरानी ड्रोनों को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है और इसके लिए उन्हें पश्चिमी सहयोगियों से आर्टिलरी सिस्टम की आवश्यकता है।

⇨ हम उसे पाक के साथ सामान्य चाहते हैं: विदेश मंत्रालय के विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत पाकिस्तान के साथ हिंसा मुक्त माहौल में सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है। और भारत का रुख नहीं बदला है।

⇨ हाल ही में पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने बताया था कि पाकिस्तान ने भारत के साथ 3 युद्धों में बहुत कुछ झेला है, और वे कश्मीर मुद्दे को सुलझाकर भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते हैं।

लेकिन भारत को जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाने की जरूरत है।

⇨ जजशिप के लिए वकीलों के बोलने की आजादी के अधिकार का सुप्रीम कोर्ट ने किया समर्थन :-

SC ने क्रमशः मद्रास उच्च न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय के लिए एडवोकेट आर जॉन सत्यम और एडवोकेट सोमेश्वर सुदर्शन के नामों की सिफारिश की थी।

सेंट्रे ने इन पर आपत्ति जताई क्योंकि ऐसा लगता था कि यह उनके सामाजिक माध्यम से पक्षपाती है

⇨ राष्ट्रव्यापी हड़ताल ने फ्रांस को प्रभावित किया

- फ्रांसीसी ट्रेन ड्राइवर, शिक्षक, रिफाइनरी कर्मचारी हड़ताल पर जाने वालों में शामिल हैं।
- वे सरकार का विरोध कर रहे हैं। सेवानिवृत्ति की उम्र 62 साल से बढ़ाकर 64 साल करने का फैसला
- पेंशन के पैसे बचाने और सरकारी खजाने को बढ़ावा देने के लिए एक सुधार में फ्रांसीसी सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दी थी।

<u>अन्य</u>

⇨ जेनिन (वेस्ट बैंक) में इस्साइल के हमले में दो की मौत

⇨ पश्चिम द्वारा अधिक गोला-बारूद की आपूर्ति किए जाने पर रूस ने वृद्धि की चेतावनी दी।

ओमीडिया पोस्ट: - कुछ पोस्टों में कुछ को सरकार की आलोचनात्मक पाया गया है। और इसकी नीतियां।

SC ने बताया कि संदर्भित संदर्भ फ्री स्पीच के अधिकार के तहत आता है और जज बनने के लिए कुछ भी आपत्तिजनक नहीं बताया गया है.

⇨ दी पर बीबीसी वृत्तचित्र "प्रचार" है और विदेश मंत्रालय की "औपनिवेशिक मानसिकता" को दर्शाता है।

बीबीसी (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन) ने एक डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन बनाई है, इसमें तत्कालीन विदेश सचिव को यह बताते हुए देखा जा सकता है कि उस समय की ब्रिटिश सरकार ने 2002 के गुजरात अधिकारों की जांच की थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि पीएम मोदी ने उस समय पुलिस बलों को वापस ले लिया और इस तरह अधिकारों में शामिल होने के कारण एमईए ने

इसे पक्षपाती और प्रचार से भरा बताया, इस बीच ब्रिटिश पीएम ऋषि सनक ने संसद में कहा कि ब्रिटिश सरकार बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से सहमत नहीं है।

2012 में → SC ने नरेंद्र मोदी को 2022 में गुजरात अधिकारों के लिए क्लीनचिट दी।

बीबीसी ब्रिटिश सरकार द्वारा वित्त पोषित है। और हाल ही में इसके बर्नर कम हो रहे हैं।

⇨ राष्ट्रीय निर्यात सहकारी समिति 3 महीने में नाम उर्वरक और डेयरी उत्पादों का व्यापार करेगी।
अमूल, इफको (उर्वरक) क्रमशः दुग्ध उत्पादों और उर्वरकों का निर्यात करने वाली पहली कुछ सहकारी समितियों में शामिल होंगी।
यह राष्ट्रीय निर्यात सहकारी समिति द्वारा पहला निर्यात होगा। यह भारत में सहकारिता के विकास को बढ़ावा देगा।
ऐसे बहुत से छोटे उत्पादक हैं जो अपने उत्पादों की मार्केटिंग का खर्च वहन नहीं कर सकते। इससे उन्हें बहुत लाभ होगा।

राष्ट्रीय निर्यात सहकारी समिति
↓
वाणिज्य मंत्रालय के तहत सहकारी उत्पादों के बाजार और निर्यात को सुगम बनाना

The ACHIEVERS IAS ACADEMY

<u>संपादकीय -1</u>

रुचि पार्टी
पीआईबी तथ्यों की जाँच करने में अच्छा हो सकता है लेकिन यह सच्चाई का एकमात्र मध्यस्थ नहीं हो सकता है।
<u>मुद्दा –</u> Meity (इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) ने PIB (Bess Information Bureake) के जरिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि को फैक्ट चेक करने का प्रस्ताव दिया है।

यह फेक न्यूज के बारे में है जो आम तौर पर इन प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रसारित होती है।

एडिशनल में क्या है?
संपादकीय में बताया गया है कि सरकार यह निर्धारित करने के लिए भूमिका प्राधिकरण नहीं हो सकती है कि समाचार क्या है, और इससे प्रेस की सेंसरशिप हो सकती है और प्रेस की स्वतंत्रता को नुकसान होगा।

<u>संपादकीय-2</u>

स्पष्टता और उद्देश्य
सफलता ने भाजपा को राजनीतिक रणनीति, चुनावी रणनीति से आत्मसंतुष्ट नहीं बनाया है।

प्रसंग

भाजपा अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल 2024 के आम चुनाव तक बढ़ा दिया गया है। बीजेपी की शुरुआती बैठक दिल्ली में संपन्न हुई 2023 में करीब 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बड़े राज्य कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं। भाजपा पहले की तरह अनुशासित नजर आ रही है। यह उन राज्यों में पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है जिनमें यह प्रासंगिक नहीं है जैसे कि तेलंगाना।

संपादकीय में पार्टी में सबसे शक्तिशाली न होने वाले राष्ट्रपति को बनाने की भाजपा संस्कृति की प्रशंसा की गई है। और हर राज्य के चुनाव में प्रयास किया।

राष्ट्रीय संक्षेप में समाचार

- ⇨ पहलवानों (विनेश फगट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक) ने बताया कि डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष को हटाने के लिए उन्होंने कई कदम उठाए हैं।
- ⇨ दिल्ली NCW (राष्ट्रीय महिला आयोग) प्रमुख स्वाति मालीवाल के साथ छेड़छाड़, दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ करने वालों को गिरफ्तार किया।
- ⇨ भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम चरण में राहुल गांधी जम्मू-कश्मीर पहुंचे
- ⇨ नीतीश ने कहा कि उन्हें बीआरएस (भारत राष्ट्र समिति) की खम्मन रैली के बारे में पता नहीं है, जिसमें सेवरल। सीएमएस व महत्वपूर्ण अपोजिशन के लोग शामिल हुए थे।
- ⇨ कानून मंत्री किरेन रिजिजुन ने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली जारी रहेगी, और सरकार के पास इसे खत्म करने की कोई हालिया योजना नहीं है।
- ⇨ जयपुर साहित्य महोत्सव जयपुर में शुरू होता है।